"प्रधानमंत्री श्री पी॰वी॰ नरसिंह राव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण"

दिनांक: 15 अगस्त, 1992 स्थान: दिल्ली

प्रिय देशवासियो, नमस्कार, हमारी आजादी की 45वीं वर्षगांठ के इस शुभअवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इस साल एक और विशेषता यह है कि हम भारत छोड़ो आन्दोलन की 50वीं जयंती भी मना रहे हैं। जिन लोगों ने इतने बड़े त्याग किये, देश के लिए और जिनके त्याग के फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली, आज हम उन्हें नमन करते हैं उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं और उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं मैं, जहां-कहीं हों देश-विदेश में वो इस अवसर पर हमें आशीर्वाद दें। एक बहुत बड़े काम को लेकर हम आगे बढ़े हैं। काम कठिन है-सफर लम्बा है। लेकिन उनके प्रेरणा से हमारा काम आसान हो जायेगा। यह मेरा विश्वास है।

साथियो, एक साल पहले मैंने आपको यहां से सम्बोधित किया था। उस समय देश की जो हालत थी, विरासत में जैसी सरकार हमें मिली थी, जो आर्थिक परिस्थिति थी, उसका मैंने थोड़ा-सा ब्यौरा आपको दिया था। एक साल हुआ उसी जद्दो-जहद में, उसी संघर्ष में, उसी प्रयास में, हम लगे हैं और यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उस प्रयास में हमें काफी कामयाबी भी मिली है, एक साल के दौरान। आज जो परिस्थिति आप देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि काफी भिन्न है पिछले साल की परिस्थिति से। देश में एक स्थिरता का चित्र आपके सामने आज नजर आता है। पिछले साल स्थिरता के बारे में कुछ प्रश्न-चिन्ह लगे थे, इसमें कोई

सन्देह नहीं है । लेकिन आज देश के भीतर या बाहर कोई यह मानता है कि यहां अस्थिरता है । स्थिरता का ये चित्र हमारे देश के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित हुआ है । और जो भी हमारा कार्यक्रम आर्थिक सुधार का और सामाजिक सामंजस्य को बनाये रखने का हमने उठाया था, वह आगे बढ़ा है । वह यसस्वी हुआ है । हालांकि उसमें बहुत कुछ आगे करना बाकी है ।

आपको यह पता है कि पिछले एक साल में देश में कोई ऐसा उथल-पुथल नहीं हुआ जिससे सारे सामाजिक ढांचे को कोई क्षति पहुंचे या ढांचा एकदम दहल जाय । छोटे-मोटे उत्पात यहां-वहां आते गये । लेकिन उन पर काबू पा लिया गया और आज एक ऐसा चित्र हमारे सामने हैं जो कुल मिलाकर शान्तिपूर्ण है । जीवन की धारा प्रशान्त चल रही है । उसमें कोई बहुत बड़े तूफान नहीं उठ रहे हैं और यह बड़ी खुशी की बात है । क्योंकि ऐसा ही वातावरण हमें चाहिए, प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए । मैंने पिछले साल सरकार की तरफ से एक नया तरीका अपनाया था, सहमति का । मै आज सोचता हूं कि वही तरीका हमारे देश के लिए ठीक है । क्योंकि जितनी समस्याएं देश की हैं, वह दलगत समस्याएं नहीं हैं । दलों से परे, दलों से ऊँचे और सारे देश की समस्याएं हैं, समूचे देश की । तो फिर उन्हें उसी प्रकार हल करना चाहिए । सभी दलों से सभी वर्गों से, सभी समुदायों से बात करके और सबसे सलाह-मशविरा करके ही इनको हल किया जा सकता है । आज भी मै यही मानता हूं कि यही तरीका अच्छा है और मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरीके को हम जारी रखेंगे ।

जहां तक की आर्थिक व्यवस्था का सवाल है, काफी हमें कामयाबी इस दिशा में हुई है । पिछले साल जो हमारी परेशानी

थी वह आप जानते ही हैं । यहां तक की हमें सोना भी अपना गिरवी रखना पड़ा था । एक हजार करोड़ से ज्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी । शायद एक हफ्ते के अन्दर हम डिफॉल्टर बन जाते । और हमारी साख एकदम राख में मिल जाती । ऐसे समय से हम आगे बढ़े हैं । कुछ सावधानी से, फूंक-फूंक कर कदम रखते हुए और आज मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी विदेशी मुद्रा सत्रह हजार करोड़ तक पहुंच गयी है । और बाहर से किसी भी चीज के आयात करने में जिसकी हमें आवश्यकता है । हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है ।

दूसरी तरफ साल भर के प्रयास के बाद अब हमारे निर्यात भी कुछ बढ़ने लगे हैं, उनमें बढ़ोत्तरी होने लगी है । उसमें थोड़ा-सा सन्देह था कि यह होगा कि नहीं । मगर महीने-डेढ़ महीने से मैं पता हूं कि हमारे निर्यात भी बढ़ने लगे हैं । इसका मतलब यह है कि हमारे यहां उद्योगों में काम चलने लगा है । उत्पादन बढ़ने लगा है और जो उत्पादन हम बाहर भेजा करते थे, आज हम पहले की तरह भेजने की परीस्थिति में आ गये हैं ।

बाहर से जो हमारे यहां औद्योगिकीकरण के लिए पूंजी लगवाने की कोशिश हम कर रहे थे उसमें भी कामयाबी हुई है । कोई तीन हजार करोड़ से अधिक तक आज संकल्प हमारे पास आ चुके हैं । थोड़ा समय लगेगा ये पूंजी लगने में । लेकिन यह बहुत बड़ी रकम है और यह केवल रकम के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि टेक्नोलोजी के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ-साथ जो हमारी देशी पूंजी है यहां के उद्योगपतियों की वह भी काफी बड़े पैमाने पर लगने वाली है । उनके जो आवेदन हैं हमारे पास आ चुके हैं और उनके हिसाब से लगता है कोई 35-40 हजार करोड़ तक पूंजी यहां देशी पूंजी लगने वाली है । जिससे

औधोगिकीकरण को और आगे तरक्की मिलेगी और उसे आगे बढ़ाया जायेगा। अभी तक महीने-डेढ़ महीने पहले तक सोचा जा रहा था कि इस साल कुछ वारिश कम होगी, कुछ परेशानी कम होगी। लेकिन अब मैं सुनता हूं कि कुल मिलाकर देश में वारिश अच्छी हुई है। अच्छी फसलें होने की आशा है और इसलिए इस बात की आशा हम करें कि एक आम खुशहाली देश में रहेगी और उस परेशानी से हम मुक्त हो जायेंगे, जो परेशानी आ जाती है, जब वारिश कम हो जाती है, सूखा पड़ता है। परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है, यह आप जानते हैं।

अब मैं एक-दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जो हमारी नीति से संबंधित हैं और मैं सोचता हूं कि उन्हें पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। मैं यह आपसे पहला सूत्र कहना चाहूंगा कि हम एक बृहत् कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बहुत बड़े कार्यक्रम में आर्थिक प्रगति के कार्यक्रम में देशव्यापी कार्यक्रम मे आठवीं पंचवर्षीय योजना जिसमें कोई साढ़े चार लाख करोड़ रूपये की लागत लगने वाली है, पैसा लगने वाला है, ऐसे कार्यक्रम में हम लगे हुए हैं। जब इतने बड़े कार्यक्रम में हम लगे हुए हों तो यह परमआवश्यक है कि हमारा ध्यान एक ही तरफ रहना चाहिए। उस पर केन्द्रित रहना चाहिए, उस कार्यक्रम पर इधर-उधर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि इस ध्यान को इधर-उधर हटाने के लिए कुछ व्यवधान आयेंगे। कुछ डिस्ट्रबेन्स आयेगा। कुछ तो लाया जायेगा जानबूझकर या कुछ परिस्थिति में आयेगा। लेकिन उन छोटी-मोटी समस्याओं को हल करते हुए भी हमारा जो केन्द्रीयकरण है, हमारे ध्यान को वो केवल हमारी प्रगति पर, हमारे विकास पर होना चाहिए और सरकार का यह संकल्प है कि ऐसा ही होगा।

दूसरा सूत्र जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार एक शक्तिशाली संस्था है। लेकिन सरकार की शक्ति का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? हमारा यह कहना है, हमारा यह मानना है कि इस शक्तिशाली संस्था की शक्ति शक्तिहीनों के लिए होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो दुर्बल हैं,

कमजोर हैं, अपनी हिफाजत आप नहीं कर सकते । जो शक्तिशाली लोग हैं, समाज में वो तो वैसे भी अपनी मदद कर लेते हैं । लेकिन सरकार को उन्हीं लोगों की मदद करनी चाहिए, मुख्यत: जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते । लेकिन जहां हम सरकार को निर्बल का बल, अन्धे की लाठी बनाना चाहते हैं । उसमें व्यवहारिक रूप से जो रुकावटें आती हैं, जो प्रश्न आते हैं उनको भी समझना चाहिए ।

आज हमारे देश में 40 साल से हम पंचवर्षीय योजनाएं चला रहे हैं । किसी भी गांव में चले जाइए वहां विकास की थोड़ी कमी हम देखते हैं । स्कूल की इमारत ठीक नहीं होती, रास्ते ठीक नहीं होते और कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग शिकायत करते हैं और वज़ातौर पर शिकायत करते हैं । दूसरी तरफ हमारे जो उद्योग हैं---बहुत बड़े-बड़े उद्योग एक-एक उद्योग में चार हजार-पांच हजार करोड़ रूपया लगने वाला है और लगा हुआ है । उनसे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है । जितना मुनाफा वापिस आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है । इसलिए उधर से भी एक तरह से मार पड़ रही है । अब दोनों तरफ लोगों का ही पैसा लगे, सरकार का ही पैसा लगे, यह हो रहा है । लेकिन नतीजा यह हो रहा है कि न वो ठीक कर पा रहे हैं, न ये काम ठीक कर पा रहे हैं । दोनों तरफ कमी हम महसूस कर रहे हैं और इसका कारण यही है कि हमारे देश में इतना पैसा नहीं है कि हम दोनों तरफ लगा सकें ।

यह कोई नई बात नहीं है । पण्डित जवाहर लाल नेहरू के जमाने से, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में सभी-सभी प्रधान-मंत्रियों के जमाने में यह हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो पैसा है, जो पूंजी है वह काफी नहीं है हमारी पूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए । और इसलिए आज हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है । मान लीजिए कि एक उद्योग है । एक बहुत बड़ा कारखाना है, जिसमें पांच हजार करोड़ लगेंगे । यह पैसा जब हम लगायेंगे तो हमारा पैसा

159

लोगों से जमा किया हुआ पैसा, बसूल किया हुआ पैसा, आपका पैसा, उसमें लगेगा । अगर यह पांच हजार करोड़ लगाने वाला कोई दूसरा रहे, कोई पूंजीपति यहां वाला, उद्योगपति और वो राजी हो जाय तो ये पांच हजार करोड़ रुपया जो हमारा लगने वाला था, सरकार का लगने वाला था, वो मुक्त हो जायेगा । वो हमारे हाथ में आ जायेगा । मैंने हिसाब लगाया है कि पांच हजार करोड़ रुपये हमारे पास रहें और किसी उद्योग में लगने वाले उस पैसे को कोई दूसरा लगाने के लिए तैयार हो जाय तो इस पांच हजार करोड़ रुपये में हम एक लाख पाठशालायें बना सकते हैं । एक प्रोजैक्ट का कोई पैसा बाहर से आ जाय या दूसरे ढंग से हम इकट्ठा कर सकें तो एक प्रोजैक्ट के पैसे से हम एक लाख स्कूल बना सकते हैं । तो आप अन्दाजा कीजिए की जो पूंजी हमारी केवल इन्फ्रास्टेक्चर में लग रही है, बिजली के प्रोजैक्ट में लग रही है, अगर उसके लिए कोई दूसरा हमें साधन मिल जाय, दूसरा सोर्स मिल जायेतो यह पैसा जो मुक्त होगा, हमारे हाथ में रहेगा । इस पैसे से हम देहात की और उन लोगों की मदद पूरी तरह से नहीं हो पा रही है कितनी मद्द कर सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर मदद कर सकते हैं । यह एक नया दृष्टिकोण है । एक दम नया नहीं है । लेकिन इस पर जो जोर है वो नया है । हम यह चाहते हैं कि यह पैसा वहां से मुक्त हो और वहां और लोगों का पैसा जाये । चाहे बाहर से जाये चाहे भीतर से आये । चाहे हमारे ही लोग जो बाहर बसे हुए हैं, भारतीय मूल के वो लायें या और कोई भी जायें अगर वो पैसा आ सके बिजली के काम में वो लग सके, सिंचाई के काम में वो लग सके, सीमेंट के कारखानों में वो लग सके, इस्पात के कारखानों में वो लग सके, तो बहुत बड़े पैमाने पर हमारा जो पैसा उसमें लगने वाला था वो मुक्त हो जायेगा । और ग्रामीण कार्यक्रमों में लगाने का हमें पूरा-पूरा मौका मिलेगा । दोनों

.......7

1512

तरफ तरक्की होगी । क्योंकि दोनों तरफ तरक्की होना आवश्यक है । तो यह जो रिप्लेसमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूंजी जहां हमारी लग रही थी वहां से हम दूसरी तरफ लगायें । उसे और वहां के लिए दूसरी तरफ से पैसा लायें, पूंजी लायें । ये रिप्लेसमेंट का जो कार्यक्रम है उससे हमारा बहुत कुछ फायदा होना वाला है । आप देखेंगे कि हमारे ग्रामीण कार्यक्रम बड़ी तेजी से अब आगे बढ़ेंगे । आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम बड़ी मुश्किल से हम 14 हजार करोड़ रुपये रख सकते थे, पांच साल में । ग्रामीण कार्यक्रमों के लिए । लेकिन अब हमने फैसला किया है कि 14 की बजाय हम उसे 30 हजार एकदम कर दें । एक ही बैठक में हमने 14 हजार से 30 हजार करोड़ कर दिया ।

तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर हम ग्रामीण कार्यक्रमों को उठा सकेंगे और आगे बढ़ा सकेंगे । मैं तो चाहता हूं कि इसे और आगे बढ़ायें । 30 हजार की बजाय अगर हम 50 हजार तक उसे ले जा सकें तो और भी अच्छा हो । इस प्रयास में हम लगे हुए है कि जो पैसा मुक्त होगा बड़े-बड़े कार्यक्रमों से, बड़े-बड़े प्रोजैक्टस से, वो पैसा हम गांवों के कार्यक्रमों में लगायेंगे । और जो पैसा लगेगा जो प्रोजैक्टस बनेगा । वो कहीं बाहर तो जाने वाला नहीं है । कई लोग घबराये हैं कि बाहर से पैसा आयेगा तो पता नहीं क्या हो ? मै कहना चाहता हूं कोई कारखाना यहां लगायेगा तो कारखाना यहीं तो लगेगा । हमारा देश छोड़ कर बाहर तो वह भागने वाला नहीं है । सड़क बनेगी तो सड़क यहीं बनी रहेगी । रेल बनेगी तो यहीं तो रहेगी । इसमें घबराने की कोई बात नहीं है । जितनी पूंजी लगे लगने दीजिए । वो हमारी हो जायेगी, अपनी हो जायेगी, देशी हो जायेगी और उससे फायदा हमें मिलेगा । जो पूंजी लगाता है वो भी थोड़ा बहुत मुनाफा हासिल करना चाहेगा । उसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए क्योंकि केवल मुफ्त में कोई लगाने को तैयार नहीं होता । इसलिए उसके लिए भी हमारी तैयारी होनी चाहिए और जो पैसा हमारे हाथ में इस तरह से मुक्त हो जाता है वो ग्रामीण कार्यक्रमों में हम लगाने को तैयार हों ।

अब मैं आप के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि पिछले एक साल में हमने गरीबों के कितने कार्यक्रम शुरू किये और जिनके बारे में मैंने पिछले साल आपके सामने निवेदन दिया था कि यह-यह कार्यक्रम हम करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे कार्यक्रम हम शुरू कर चुके हैं और वह आगे बढ़ रहे है। पहला कार्यक्रम मैंने कहा था 1700 हमारे ब्लाक हैं, जिसमें बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को अन्न पहुंचाने के लिए हम एक नया कार्यक्रम लेनाचाहते हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पहली जनवरी से हमने यह कार्यक्रम बड़ेपैमाने पर साढ़े सत्तरह सौ ब्लाक में हमने शुरू किया है। राजस्थान से मैंने इसकी शुरूआत की थी और हर जगह यह कार्यक्रम चल रहा है। वहां दुकानों की कमी थी, सस्ते दुकानों की। वो कोई 9-10 हजार दुकानें तो हमने ये 6-7 महीने में खोल रखी हैं। शायद और 10 हजार हम खोलने वाले हैं, अगले कुछ महीनों में। फिर वहां हम 20 लाख टन अनाज ज्यादा दे रहे हैं, पहले से। ताकि पहले जो उनको कम मिलता था वो अब ज्यादा मिले और उस कार्यक्रम को हमने लिंक कर दिया है, जोड़ दिया है, जवाहर रोजगार योजना से। और जवाहर रोजगार जोजना के लिए विशेषकर 8 लाख टन अनाज दिया है। ताकि जो जवाहर रोजगार योजना है, मजदूरी पाते हों, उनकी मजदूरी अंशतः उसका एक भाग अनाज में मिले। ताकि फिर उसे भुखमरी का सामना करना न पड़े। और सस्ते दामों में उसे अब अनाज मिलता है तो हमारे हिसाब से ऐसा अनुमान हैकि एक-एक आदमी के लिए एक-एक दिन दो किलो चावल या गेहूं मिल सकेगा, उसकी मजदूरी के एक भाग के रूप में। और जो समस्या भुखमरी की वहां हम पाते हैं वह समस्या पर काबू पा लिया जायेगा।

दूसरा कार्यक्रम हमने, मैंने यह कहा था, पिछले साल कि हमारे जो कारीगर हैं गावों में वह बहुत पुराने औजार से काम कर रहे हैं।

153

उनकी उत्पादकता नहीं बढ़ रही है और गरीबी अपनी दूर करने के वह बड़े-बड़े शहरों में जाकर बस रहे हैं और वहां पर एक समस्या खड़ी हो रही है । तो मैंने कहा था कि इन औजारों को ठीक करने के लिए आधुनिकीकरण के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम बनाने वाले हैं । मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि वह कार्यक्रम शुरू हो चुका है । इस एक साल में, जो चल रहा है साल, इस एक साल के अन्दर में कोई 40 हजार 50 हजार गावों में यह कारीगरों को आधुनिक औजार देने का कार्यक्रम पूरा करने जा रहे हैं और अगले चार-पांच वर्ष में सारे देश में यह कार्यक्रम होगा । यह बहुत बड़ा, बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है । क्योंकि जब तक वहां का कारीगर-गावों का कारीगर गांवों में नहीं रहता और गांव के काम नहीं करता तो गावों की तरक्की नहीं होगी । और वह पिछड़ा ही रह जायेगा । तो यह कार्यक्रम भी शुरू किया गया है ।

इसके बाद मैंने यह भी कहा था कि हमारे गावों में जो रैवन्यू रिकोर्ड्स हैं । रिकॉर्डस आफ राइटस कौन जमीन किसकी है, किस पर कब्जा है, क्या है ? यह लिखने से जो धांधली होती है, उसीसे मुकद्मेबाजी होती है । उसीसे कभी-कभी खून-खराबा भी होता है । तो उनको ठीक करने के लिए हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उठायेंगे । मुझे फिर यह कहने में आनन्द हो रहा है कि वह भी हम कर रहे हैं और उसके लिए भी एक टीम बन चुकी है । हम राजस्व मंत्रियों को सबको बुलाकर यह कह रहे हैं कि एक साल के अन्दर या दो साल के अन्दर एक समयबद्ध तरीके से यह पूरा काम हो जाना चाहिए । सीलिंग के बारे में मैंने कहा था कि जितनी जमीन है सरकार के पास सीलिंग में ली हुई और जिसका वितरण नहीं हुआ है, उसको पूरी तरह से बांट दिया जायेगा । यह काम भी लगभग पूरा हो गया है । एकदम पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा और बाकी है । लेकिन बड़े पैमाने पर लगभग कोई दो लाख एकड़ जमीन अब एक बांटी जा चुकी है और अगले 3-4 महीनों में यह संकल्प है कि इसके बाद हमारे देश में कोई ऐसी जमीन न रहे जो बांटने के लिए योग्य हो और बांटी न जाए । सारी

.....10

154

जमींन बांटी जायेगी-भूमिहीनों में । यह कार्यक्रम भी पूरा किया जायेगा । मैंने कहा था कि जो बैकवर्ड क्लासिस, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए एक कॉरपोरेशन बनाया जायेगा, एक निगम बनाया जायेगा उनकी तरक्की के लिए । वह भी बन चुका है । यह कहते हुए मुझे खुशी होती है कि दो सौ करोड़ की उसकी धनराशि से यह शुरूआत उसकी हुई है और उससे पिछड़े वर्गों का फायदा होने के लिए पूरा कार्यक्रम बन चुका है ।

जो इन्डस्ट्रीयल सैक्टर है, जो हमारे मजदूर भाई हैं आज की परीस्थिति में जो तबदीलियां आ रही हैं, हो सकता है कि कहीं उन पर असर पड़े तो उस असर से उनका बचाने के लिए हमने एक नेशनल रिन्यूवल फण्ड का गठन किया है । जिसमें कोई दो हजार दो सौ करोड़ रुपया हमारे पास है । जहां-कहीं हमारे मजदूर भाइयों पर कोई बुरा असर हो या उनकी रोजगारी का सवाल उठ खड़ा हो जाय तो इस बड़ी निधि से हम उनकी पूरी मद्‌द करेंगे । और यह देखेंगे कि उन पर कोई परेशानी न आये और जो भी उनको रिट्रेनिंग वगैरह करने के जो कार्यक्रम है वो सारे कार्यक्रम इन निधि से अन्जाम दिये जायें और उनको कोई परेशानी न हो । और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं किसान भाइयों के लिए जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं । जहां बिजली नहीं पहुंची है और शायद पहुंच भी नहीं सकती है, अगले पांच दस साल में । तो उनके लिए हमने सौर ऊर्जा का एक कार्यक्रम बहुत बड़ा बनाया है । जिसके लिए कोई आठ सौ करोड़ रुपया हमने पंचवर्षीय योजना में रखा है, पहली बार । इससे पहले कभी इतना पैसा नहीं रखा गया था । और इतना ध्यान नहीं दिया गया था । क्योंकि हमारे यहां सूर्य भगवान, ऊर्जा के सबसे बड़े साधन हैं । सबसे बड़ा उद्‌गम हैं । और उसका पूरा-पूरा फायदा हमने उठाना है ।

यह टेक्नोलॉजी का प्रश्न था । सिद्धान्ततः तो यह सम्भव है । लेकिन जब टेकनोलॉजी की बात आती है तो कहा जाता है कि यह जो पम्प बनते हैं यह बहुत कीमती होते हैं और हमारे किसान भाई इन्हें नहीं खरीद

सकते । आज हमारे देश में जो शोध हुआ है, हमारे साइन्टिस्ट जो शोध कर रहे हैं, उसके हिसाब से आज कहा जा सकता है कि इसकी कीमत को घटा कर हमारे किसान भाई इसको खरीदने के योग्य हों । इस काबिल इसे बनाने के लिए कोशिश हो रही है। वह भी कामयाब हुई है । जिसका नतीजा यह होगा कि दूरदराज के इलाके में जहां बिजली नहीं पहुंच सकती । वहां यह स्टैन्टअलोन जिसको कहते हैं कि एक कुंआ है, उस कुएं पर यह पैनल लगेगा । और बस सौर पैनल, सूर्य की ऊर्जा को एकदम लेकर उस गर्मी को बिजली में तबदील करके पम्प को चलाने का जो कार्यक्रम है यह बहुत बड़े पैमाने पर यह होगा । और एक-एक किसान का इसमें फायदा होगा । और गांवों के लिए भी जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो बिजली की आवश्यकता होगी, वो वहां पैदा की जायेगी । जहां जहां ये प्रयोग हुए हैं, वहां के किसानों का कहना है कि यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है । क्योंकि जो मामूली बिजली है वह कभी बन्द होती है, कभी खुलती है, कभी दो घन्टे चलती है, कभी एक घन्टा चलती है । और उनके खेतों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है । खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए यह जो नई ऊर्जा का कार्यक्रम है, वो उन्हें बहुत पसन्द आया है । यह कहते हुए भी मुझे बड़ी खुशी होती है। और इसको हम बहुत बड़े पैमाने पर उठाने वाले हैं। और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैंने कहा । बहुत बड़े पैमाने पर आज हम ऊसर क्षेत्रों को, हमारे देश में कई ऊसर क्षेत्र हैं, गांव-गांव में पड़े हुए हैं, उनको विकसित करनेकी कोशिश कर रहे हैं । उनमें पेड़ लगाना उनका हरा भरा करना या उनको उत्पादन योग्य बनाना जिस किसी तरह से यह हो सके उनका विकास करना यह बहुत बड़ा कार्यक्रम हम उठा रहे हैं । लाखों-लाखों लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा और इसके लिए मैंने एक नया विभाग भी बनाया है और उस पर बड़े

156

ध्यान से देखा जायेगा और वह कार्यक्रम उठाया जायेगा । यह अभी हमारी इस योजना में बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रावधान किया गया है ।

अब मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक इनके लिए जो कार्यक्रम पिछले एक वर्ष में उठाये गये हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर और बड़े विस्तृत ढंग से उठाये गये हैं । एक तो बना है शैड्यूल्डकास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक निगम और महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय निगम इन दोनों निगमों को काफी अधिकार दिये गये हैं कि उनके जो कारोबार हैं उनकी जो उनका जो कर्तव्यहै, उनके पालन में वो पूरी तरह से काम करे और प्रभावी ढंग से काम करें । ऐसे सारे अधिकार उस नियम उस निगमों को दिये गये हैं और साथ ही साथ माइनॉरटीज़ कमीशन को जो अल्पसंख्यकों का आयोग है आज तक वह एक आयोग की तरह से ही था । सारे जितने आयोग हैं यह एक और आयोग था । लेकिन अब की बार उसे हमने एक कानूनी दर्जा दिया है । जिससे उसके सारे अधिकार पूरी तरह से लिखे जायें । और बताये जायें कि यह यह इनके अधिकार हैं । और इन अधिकारों को चलाने के लिए इनका कार्यान्वयन करने के लिए उनको पूरी तरह से छूट है और इस अधिकार को चलाने में जैसे और निगमों को स्टेट्यूटरी निगमों को अधिकार दिया गया वह ही अधिकार इनको भी दिया गया है । हम यह आशा करते हैं कि इसका बहुत बड़ा उपयोग अल्पसंख्यकों को मिलेगा । उनकी रक्षा के लिए और उनकी तरक्की के लिए ।

इसके बाद मैंने अभी-अभी कहा जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कॉरपोरेशन बनाया जा चुका है । हम यह चाहते हैं कि यह सफाई यह जो भंगी भाई हैं, उनका यह जो अपमानास्पद जैसा पेशा है उसे

157

इस देश में समाप्त किया जाये । आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने कोई 560 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है । आवश्यकता पड़ेगी तो इसे बढ़ाया भी जायेगा, बढ़ाया भी जा सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है । और साथ ही साथ सफाई कर्मचारी, हमारे जो लाखों

इस देश में उनकी जो समस्याएं हैं उनको देखने के लिए, उनपर गौर करने के लिए हमने एक आयोग बनाना का निश्चय किया है। वह आयोग का गठन अभी हो रहा है । अगले कुछ दिनों में वह पूरा बन जायेगा और उससे इस वर्ग के लोग जो उपेक्षित रहे हैं, अब तक, उनका भला हो सकेगा और उनकी समस्याओं को पूरी तरह से देख-समझ कर, देख-परख कर उनका समाधान ढूंढने की कोशिश पूरी हो जायेगी ।

अब मैं उन थोड़े बहुत उन प्रश्नों पर आता हूं जो हमें विरासत में मिले हैं और जिनसे हम निपट रहे हैं । पंजाब के बारे में आप जानते हैं कई साल के बाद वहां एक राज्य सरकार बनी । जनता की सरकार, जिनको लोगों ने चुना । और यह कहते हुए मुझे खुशी होती है कि सरकार आज बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों का पूरा-पूरा योगदान वह प्राप्त कर रही है । और यह देख कर मुझे बड़ी खुशी है । मैं यह भी आपसे कहना चाहूंगा कि पंजाब के सिलसिले में जो भी समस्याएं उठ खड़ी हुई थीं उनपर पूरी तरह से हम लोग लगे हुए हैं, उनका हल कैसे ढूंढा जाय ? जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए । सोच समझकर करना चाहिए । सब लोगों से सलाह मशविरा करने की कोशिश कर रहे हैं । हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है । मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है उसमें हम लगे हुए हैं । आप देखेंगे कुछ ही समय में थोड़ा बहुत आपको झलक मिलेगी कि क्या हम करना चाहते हैं और किस दिशा में हम चल रहे हैं । इस बीच में वहां लॉ एण्ड आर्डर का जो कार्यक्रम है वह भी सुचारू रूप से चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कई कामयाबियां उसको मिल रही हैं । ठीक है कि आज भी लोग वहां मारे जा रहे हैं । यह कोई अच्छी बात नहीं कोई खुशी की बात नहीं है । सबको इससे सदमा होता है, सबको तकलीफ

होती है । लेकिन जबी हम इस जद्दो-जहद में लगे हुए हैं तो फिर थोड़ा बहुत इस प्रकार का नुकसान उठाना ही पड़ेगा । लेकिन कुल मिलाकर वहां की हालत संतोषजनक है और मैं उस दिन का इन्तजार कर रहा हूं जबकि पंजाब पूरी तरह से अमनोअमान हो जायेगा । अब यह अलग बात है कि हमारे सरहद से उस पार से उनको जो मदद मिलती है वह अब भी जारी है यह कहते हुए मुझे खेद होता है कि बावजूद इसके कि हम उनको बार-बार कह रहे हैं कि ऐसी हरकतें न कीजिए वह बराबर किये जा रहे हैं ।

आसाम में परिस्थिति सुधरी है । इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है । बड़ी हद तक सुधरी है और जो हिंसा के पक्ष में थे, हिंसात्मक कार्यवाहियों में लगे हुए थे, उन्होंने हिंसा त्यज कर राष्ट्रीय मुख्य-धारा में आना कबूल किया है । उनके अधिकांश लोग आ चुके है । उनके हथियार भी दे दिये हैं वापिस । लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जो संघर्ष को जारी किये हुए रखे हुए हैं । उनसे निपटना पड़ेगा और वह काम वहां हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि थोड़े समय में ही शायद उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया जायेगा ।

कश्मीर का मामला लटक रहा है कई दिनों से । कभी-कुछ-कभी कुछ । लेकिन पूरी तरह से देखने पर ऐसा लगता है कि काबू में है । मुझे इससे संतोष नहीं है । क्योंकि जब तक भारत का एक-एक कोना डेमोक्रेटिक सैटअप में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं आता तब तक हमें संतोष नहीं होगा । मैं यह कहना चाहता हूं, स्पष्ट रूप से कि जब कभी भी वहां के हालात ऐसे होंगे कि वहां चुनाव किये जा सकते हों, शान्तिपूर्ण ढंग से, बराबर वहां चुनाव हम कराना चाहते हैं, कराना चाहते हैं । और एकदम फ्री होंगे, एकदम आजाद एकदम स्वेच्छा के साथ वहां चुनाव होंगे और भारत के संविधान के तहत ऐसे चुनाव करके वहां भी हम जनता की सरकार की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं ।

159

मण्डल कमीशन के सिलसिले में जो सवाल उठखड़ा हुआ था। उसके बारे मैंमैंकह चुका हूं। अभी तो वह सर्वोच्चन्यायालय में है। कुछ ही दिनों में फैसला आ जायेगा। उसके अनुसार काम होगा। हमारा तो यह रवैय्या रहा है, सरकार का यह रवैय्या रहा है, सरकार का यह फैसला है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए और उनमें भी जब एक गरीब और एक अमीर दो ऐसे केण्डीडेट हों तो गरीब को पहले मिलना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर सारे जो नौकरियां हैं वह पिछड़े वर्गों के ही जुमरे को मिलने चाहिए। उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। यह हमारा फैसला है और जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी हमने 10 प्रतिशत आरक्षण दे रखा है। यहअभी जैसा मैंने कहा सर्वोच्च न्यायालय के सामने हैं जिसके अनुसार हम इस पर कार्यान्वयन करेंगे।

अब मैं आता हूं उस प्रश्न पर जोअभी-अभी हाल में कुछ दिनों पहले एक भयानक स्वरूप इख्तयार करना चाहता था। लेकिन कृपा है लोगों की, उन लोगों की जो इसमें काम कर रहे थे, उनकी भलमंशी से उस संकट को देशव्यापी संकट को हम टाल सके हैं। मेरा मतलब है अयोध्या की समस्या से। ये समस्या कोई मन्दिर या मस्जिद की समस्या नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इसको केवल मन्दिर और मस्जिद की समस्या समझना भ्रामक होगा, गलत होगा। यह समस्या है हमारे देश की एकता की समस्या। हमारे देश और हमारे समाज में जो सामन्जस्य सदियों से चला आता है, आज भी लाखों गावों में जो चल रहा है। उसकी रक्षा करने की समस्या है, उसको बनाये रखने की समस्या है। जो भी हम कदम उठायेंगे, उनमें से एक भी कदम गलत होगा तो मन्दिर और मस्जिद की समस्या को बाजू रखिये देश में क्या होगा इसका भी हमें विचार करना चाहिए। और बहुत सोच समझकर हमें इसमें कदम उठाना है। एक बार इस खतरनाके नुक्कड़ पर आने के बाद हम इसे डिफ्यूज़ कर पाये हैं। कुछ और समय बाकी है, उसके भीतर सभी

160

लोगों से वार्ता करके सलाह-मशविरा करके हम कोई सैटलमेंट करना चाहते हैं। सरकार की यही पालिसी है, नीति है कि इस समस्या पर सबसे बातचीत करके एक हल निकाला जाय। हल ऐसा हो कि दोनों धर्मावलम्बियों की जो भावनाएं हैं, उनका आदर हो। किसी कारण यह अगर नहीं हो पाया तो अदालद का जो फैसला होगा वह सबपर लाजिम होगा। और हमें पूछिये तो हमारा यह फार्मूला है, हमारी यह इच्छा है, हमारी यह नीति है कि वहां मन्दिर बने। भव्य मन्दिर बने लेकिन मजिस्द न टूटे यह हमारा फार्मूला है, यह हमारा निश्चय है और हमारा फैसला है। यह इसी तरह से हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। {तालियां} फिर वार्ता में जो कुछ होगा, सब लोग मिलजुल कर जो कहेंगे उस पर से कोई हल निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। देशवासियों को यह जानना चाहिए कि भारत सरकार क्या कर रही है और किस संकल्प से कर रही है और हमारा लक्ष्य क्या है।

अभी विदेश के सिलसिले में दो बातें कहूंगा। विदेश नीति हमारी जो पहले से चली आती, वह अपनी जगह कायम है। लेकिन हमें बहुत सक्रीय बनना है और हमने फैसला किया है कि उसी सक्रियता से हम काम करेंगे। पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं। केवल पाकिस्तान के सिलसिले में यह कहना मुशकिल है। चार-चार बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मेरी बातचीत हो चुकी है। बात बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब कभी कोई आगे कदम उठाने की नौबत आती है, ऐसा अवसर आता है, कहीं न कहीं से कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है, जिससे हम जहां के वहां रह जाते हैं। यह कौन कर रहा है? यह क्यूं कर रहा है? कैसे यह हो रहा है? यह अपना अन्दाजा लगाने की बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें यह वार्ता जारी रखनी होगी और इस मामले में भी हमारा दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए कि कश्मीर भारत का एक अविभाज्य अंश है। हमारा हिस्सा है और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं

कर सकती । इसको मान कर चलना है और इसके बाद जो भी समझौता हो जो भी अच्छी बात हो हमारे संबंधों को ठीक करने के लिए वह हम करते रहेंगे । लेकिन यह हमारा बोटम लाइन होगा ।इसके बारे में किस को संदेह नहीं होना चाहिए ।

दूसरे देशों के साथ जैसे अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस वगैरह और जो इससे पहले सावियत यूनियन, सोवियत संघ जो हमारा मित्र था, परममित्र और उसके टूटने के बाद जितने नये देश बने हैं उन सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं । वहां के कई राष्ट्राध्यक्ष यहां आ चुके हैं । मुझे भी वहां जाने का निमन्त्रण है और उनके साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे और गहरे होते जा रहे हैं ।

गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन में अब भारत को पहले से अधिक सक्रीय होना होगा । यह हम जान चुके हैं । क्योंकि पिछले दो तीन साल में आन्दोलन के कार्यक्रम मे कुछ मन्दापन आया है, कुछ सुस्ती आयी है । आज हम उसे फिर से सक्रीय बनायेंगे ।

अब मैं अन्म में आपसे दो तीन बातें निवेदन करूं । इस देश में जहां अधिकांश लोग ईमानदार है, प्रमाणिक है । कुछ बेइमानों की भी कमी नहीं हैं । और बैंकों का मसला लेकर स्टौक का मसला लेकर जो इधर बेइमानी का बाजार गर्म हुआ । लोगों ने लूटना चाहा, बेज़ा फायदा उठाना चाहा, यह अचानक यह प्रकरण जब शुरू हुआ तो यह पता लगा कि अब इसको पहले ही पहले ही इन पर कार्यवाई होनी चाहिए । इस्तकबल कि वो फिर अपने पूरे हिसाब किताब को ठीक करके लीपा-पोती करें । हमने यह कदम उठाये यह खबर हमें मिलते ही सरकार को मिलते ही, जितने कदम कड़े से कड़े कदम हमें उठाने चाहिए था, हमने कदम उठाये हैं । उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं । एक स्पेशल कोड बन चुका है। पूरे जोर-शोर के साथ उसमें इन्वेस्टीगेशन हो रहा है और यह मैं आपसे कहना चाहता हूं जितने इसकी जड़ में आयेंगे, जितने इसमें दोषी ठहरेंगे, उनपर कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जायेगी और कड़ी से कड़ी सज़ा उनको अवश्य मिलेगी । यहां तक कि इन चीजों को

रोकने, आगे के लिए कैसे इसकी रोकथाम हो, यह हमारा पार्लियामेंट ही देखे। पार्लियामेंट के सदस्यों की एक हमने कमेटी कठित कराई है जो कल से या आज से काम अपना शुरू करेगी और उन्हीं के कहने पर सरकार चलेगी। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर एक बार कहूंगा कि इस देश में, इस सरकार में, जहां तक हमसे बन पड़ा, बेइमानी के लिए कोई जगह नहीं रहेगी और बेइमानों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। किसी को बख्शा नहीं जायेगा। चाहे कितना बड़ा आदमी हो। लेकिन उसको बराबर कानून की सजा कानून की रूह से जो सजा उसको मिलनी चाहिए, वो मिलकर रहेगी, वो दी जायेगी। इसमें कोई कमी नहीं की जायेगी यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

एक दूसरा मैं, दूसरा संकल्प है कि आज अगले कोई दो-तीन साल तक हमें शान्ति की आवश्यकता है। हमारी, हमारे देश में ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को जोड़ती है। ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को तोड़ती हैं। क्या यह नहीं हो सकता कि अगले दो तीन साल तक हम एकमॉरोटोरियम कर दें? एक बन्दी कर दें, ऐसी समस्याओं की जिनसे देश टूटता है? और हमारा ध्यान उसी पर केन्द्रित हो उनी समस्याओं पर, जो देश को जोड़ती हैं। अगर यह हो सकता है तो मैं करना चाहता हूं, मैं सबसे यह अपील करता हूं कि ताक पर रखें अगले तीन साल तक यह तोड़ने वाली समस्याओं को-तोड़ने वाले प्रश्नों को? भूल जायें वह, रहेंगे अपनी जगह। जब उनको फिर से हाथ में उठाना है, उठायेंगे। जबझगड़ना है, झगड़ेंगे। लेकिन अगले तीन साल तक झगड़ने की कोई गुन्जाइश नहीं है। सारी समस्याएं इस देशकी हैं, समूचे देश की हैं, समूचे समाज की हैं। जो समस्याएं हाथ पर हैं उनको हल करेंगे। इस मॉरोटोरियम की जो मैं अपील कर रहा हूं उसे मैं चाहता हूं कि दूसरी पार्टियां और लोग उसको कबूल करेंगे और ऐसा होगा तो देश का बड़ा कल्याण होगा।

163

एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा वचन है आपको कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। जल्दबाजी में जो फैसले किये जाते हैं, सरकार की तरफ से उनसे परेशानी ज्यादा बढ़ती है, बाद में। जब फैसला होता है, लगता है, बहुत अच्छा किया। लेकिन बाद में उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उनसे बहुत परेशानी देश को होती है। जल्दबाजी में नहीं करेंगे-सोच समझकर करेंगे। जो कदम उठायेंगे-पक्का कदम उठायेंगे। एक बार आगे कदम रखने के बाद फिर पीछे नहीं हटेंगे। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। फिर हमारा दृष्टिकोण किसी दलगत दृष्टिकोण नहीं रहेगा। हमारा दृष्टिकोण समूचे देश के कल्याण के लिए रहेगा। समूचे समाज के लिए रहेगा और यह दृष्टिकोण अपना कर हम चलना चाहते हैं।

इन तीनों सूत्रों को आप सोचें इन पर गौर करें, मैं यह चाहता हूं। ऐसा समय आया है एक राष्ट्रीयस्तर पर ऐसी एक सहमति बने-इन तीनों सूत्रों पर और हम सब मिलकर कन्धे-से-कन्धा मिलाकर आगे बढ़ें और अगले तीन चार साल में जो भी हमारी समस्याएं विरासत में मिली हैं, उनको तो हल करेंगे ही। लेकिन देश की प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा-बड़ा प्रयास हम करेंगे। बृहत प्रयास करेंगे। तो दूसरे देशों की बराबरी में हम आ सकेंगे नहीं तो अभी तक पिछड़ गये हैं और भी पिछड़ जायेंगे। हम अपनी छोटीछोटी उलझनों मेंउलझे रहेंगे। तो यह ठीक नहीं होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़े अदब के साथ और इन्हीं बातों पर आप सोचिये आप अगर इन बातों को इन तीनों सूत्रों को आशीर्वाद देंगे। तो, तो किसी मजाल नहीं है कि वह इन्कार कर सके। मैं देशवासियों का आशीर्वाद चाहता हूं उनका समर्थन चाहता हूं इन तीनों सूत्रों के लिए और मैं यह आशा करता हूं कि उनका समर्थन मुझे मिलेगा।

अब मैं बहुत ज्यादा समय आपका ले चुका हूं। बहुत सी बातें कहने की लेकिन कई अवसर मिलेंगे। आज के अवसर पर एक आशा-जनक हमें भविष्य की तरफ बढ़ना है। कई बातें अच्छी हुई हैं। कुछ बुरी बातें भी हुई हैं जिनका निराकरण करना है। तो कुल मिलाकर एक आशाजनक

भविष्य हमें नजर आता है और उस की तरफ बढ़ने का मैं आवह आह्वान आपको देता हूं, निमन्त्रण आपको देता हूं और आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं ।

जय हिन्द ! जय भारत ! ((तालियां))